

जनपद में महिला सशक्तिकरण में महिला डेरी का योगदान

*डा० हेमा मेहरा

प्रस्तावना—नैनीताल जनपद में महिला डेरी विकास का प्रारम्भ 1994 में हुआ। महिला डेरी विकास द्वारा महिला दुग्ध समितियों के गठन में ग्रामीण महिलाओं को सहकारिता के ढाँचे में सम्मिलित करके उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए सरकार द्वारा डेरी विकास योजना को प्रारम्भ किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों के जीवन यापन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। पशुपालन व्यवसाय में एक सार्थकता पूर्ण पहल के रूप में सरकार ने महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से इस परियोजना को प्रारम्भ किया। दुग्ध व्यवसाय मूलतः महिलाओं के द्वारा ही चलाया जाने वाला व्यवसाय है। अतः महिलाओं के दृष्टिकोण में वैज्ञानिक परिवर्तन लाने, उनकी जानकारी में वृद्धि करने तथा काम करने की उनकी मूल क्षमता का लाभ उठाना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है।

उत्तराखण्ड में महिला डेरी विकास का प्रारम्भ सन् 1994-95 में एक परियोजना के रूप में प्रारम्भ हुआ। इस परियोजना के अन्तर्गत 8 जिलों को सम्मिलित किया गया है तथा भारत सरकार व युनिसेक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उद्देश्य— उक्त शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है।

- 1— आर्थिक रूप से दुर्लभ ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- 2— महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता व आत्मशक्ति का विकास करना।
- 3— महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक समानता एवं न्याय उपलब्ध कराना।

शोध विधि— उक्त शोध पत्र द्वितीयक संमको पर आधारित है।

द्वितीयक संमको का संकलन दुग्ध डेरी, उपनिबन्धक सहकारी समितियाँ, लालकुआँ दुग्धसंघ, जिला ग्राम्य विकास क्षेत्रीय निबन्धक सहकारिता विभाग से लिया जायेगा।

दुग्ध व्यवसाय के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के कुछ भागों में जहाँ महिलाओं को नीति निर्धारण तथा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी दी गई है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश इत्यादि सम्मिलित हैं वहाँ पर महिलाओं ने अपनी क्षमता से अभूतपूर्ण कार्य किए हैं। रोजगार एवं आय की दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं के लिए जनपद नैनीताल के ग्रामीण अंचल में दुग्ध व्यवसाय महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

योजना आयोग की पूर्व सदस्यता सुश्री मीरा सेठ के अनुसार — दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है परन्तु शैक्षिक, सामाजिक, रूढ़िवादी एवं पारस्परिक व्यवस्थाओं के कारण उनके नेतृत्व करने की क्षमता की कमी के कारण उनकी समुचित भागीदारी नहीं हो पायी। पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में महिला डेरी परियोजना सहकारिता के माध्यम से प्रारम्भ किया है।

*एसिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग रा० महा० वि० गंगोलीहाट पिथौरागढ़,

इन राज्यों के जनपदों में 2705 महिला सहकारी दुग्ध समितियाँ गठित हो चुकी हैं। महिला डेरी परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही कृषक परिवार/दुग्ध व्यवसाय में संलग्न परिवार की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की एक योजना है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का गठन कर महिलाओं को सदस्य बनाते हुए उन्हें दुग्ध विक्रय करने की समुचित व्यवस्था ग्राम्य स्तर पर ही उपलब्ध करायी जाती है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ (जिसमें मात्र महिलाएं ही सदस्य,पदाधिकारी एवम् श्रमिक हैं) का गठन महिलाओं की आय में सार्थक वृद्धि करना तथा उन्हें कार्य परक शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वस्थ, पोषण, स्वच्छता व परिवार कल्याण जैसे विषयों के प्रति जागरूकता विकसित करना है। दुग्ध सहकारिता में मुद्रा का बहाव शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ होता है जबकि अन्य कार्यक्रमों में मुद्रा का बहाव ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ होता है।

महिला दुग्ध समितियों में बचत की भावना जागृत करने एवं अतिरिक्त आय के साधन सृजित करने हेतु स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है। प्रत्येक समूह को अधिकतम दस हजार रुपये की दर से मैचिंग ग्रांट उपलब्ध करायी जाती है। दुग्ध समितियों के गठन हेतु विभिन्न मद के अन्तर्गत प्रत्येक दुग्ध समिति को प्रथम तीन वर्षों में क्रमशः 40,08,05 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है

नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० लालकुआ (नैनीताल)

तालिका 1

महिला डेरी विकास के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति आख्या

क्र.सं०	विवरण	2010.11	2011.12	2012.13	2013.14	2014.15	2015.16	2016.17 की उपलब्धि	
								माह अप्रैल 2016	
								माह में	माह तक
1	कार्यरत समितियाँ	47	48	52	54	57	59	59	59 (25.53)
2	सदस्यता	2423	2552	2677	2780	2890	3310	3310	3310 (36.60)
3	घोर सदस्यता	1770	1791	2125	2191	2310	2327	2327	2327 (31.46)
4	महिला अध्यक्षों की संख्या	47	48	52	54	57	59	59	59 (25.53)
5	प्रबन्ध समितियों में महिलाओं की संख्या	394	403	436	460	483	518	518	518 (31.47)
6	औसत दुग्ध उपार्जन (ली० प्रति दिन)	3630	3735	4201	4246	4474	5603	6095	6095 (67.90)
7	प्रति समिति औसत दुग्ध उपार्जन (औ० दै०ली०)	77.23	77.81	80.79	78.63	78.49	94.97	103.31	103.31 (33.76)
8	स्वयं सहायता समूहों का गठन								
	(क)बी०पी० एल समूह	59	59	59	59	59	59	-	59
	(ख) ए०पी० एल समूह	35	35	35	35	35	35	-	35

स्रोत नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० लालकुआ नैनीताल, प्रगति विवरण वर्ष 2016-17

उपरोक्त तालिका 1 से स्पष्ट होता है। कि 2010-11 की तुलना 2016-17 के आंकड़ों से करने के उपरान्त निम्न वृद्धि का प्रतिशत पाया गया। कार्यरत समितियों में 25.53 एसदस्यता में 36.60, पोरर सदस्यता(प्रतिदिन दूध देने वाले सदस्यो की स0) में 31.46, महिला अध्यक्षों की संख्या में 25.53, प्रबन्ध समितियों में महिलाओं की संख्या में 31.47, औसत दुग्ध उपार्जन (ली0 प्रति दिन) में 67.90 प्रति समिति औसत दुग्ध उपार्जन (औ0दै0ली0) में 33.76 ।

उक्त उपलब्धियों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त परियोजना निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है, और जनपद के पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा रोजगार सृजन करने में भी योजना सहायक सिद्ध हो रही है।

महिला डेरी विकास योजना के तहत 59 महिला दुग्ध समितियाँ वर्तमान में कार्यरत है। जिसमें प्रतिदिन प्रति समिति औसत दुग्ध उपार्जन 103.31 (औ0 दै0 किग्रा0) प्राप्त होता है। महिला डेरी विकास योजना द्वारा संचालित 94 स्वयं सहायता समूह वर्तमान में कार्यरत है। उत्तराखण्ड में उद्योगों का लगभग अभाव सा है। इसलिए उत्तराखण्ड (पर्वतीय क्षेत्र) की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन पर ही निर्भर है। यहाँ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि, ईंधन, पानी एवं चारा आदि समस्त कार्य महिलायें ही करती हैं फलस्वरूप महिला आधारित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रम इत्यादि उत्तराखण्ड में अधिक सफलतापूर्वक चलायी जा सकती हैं।

महिला डेरी परियोजना के अन्तर्गत संचालित कार्यों का विवरण

- 1- महिला दुग्ध समितियों का गठन।
- 2- महिला दुग्ध समितियों में प्राथमिक चिकित्सा / कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना।
- 3- उन्नतिशील दुधारू पशु हेतु बैंकों से ऋण मुहैया कराना व बैंक ऋण का 33 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराना।
- 4- दुधारू पशुओं एवं बछिया/ पड़िया के बीमा हेतु सहायता।
- 5- महिला दुग्ध समिति, प्रबन्ध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण।
- 6- पशुपालन एवं चारा विकास।
- 7- सामान्य जागृति शिक्षा, प्रेरणा तथा साक्षरता।
- 8- महिला सचिव/टैस्टर /कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राथमिक चिकित्सा कार्यकर्ता प्रशिक्षण।
- 9- वर्कशाप व सूचना प्रसारण।
- 10- क्रैच (शिशु पालन गृह) की स्थापना।
- 11- बायोगैस व बायो कम्पोस्टिंग की सुविधा उपलब्ध।

निष्कर्ष- उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जनपद की ग्रामीण अंचल में दुग्ध उत्पादन समितियां महिलाओं को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रही है महिलाओं की आय में वृद्धि हो रही है साथ ही रोजगार का सृजन भी हो रहा है जिसके कारण महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ विचारों में परिवर्तन आ रहा है महिलाओं के विचारों में परिवर्तन आने से ही विकास को गति मिल सकती है।

सन्दर्भ—

- 1— ऑंचल, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, दिनांक 30/12/2015.
- 2— महिला डेरी विकास उत्तराखण्ड, लोअर माल रोड अल्मोड़ा द्वारा जारी विवरण।
- 3— दुग्धशाला विकास विभाग 05/07/2015
- 4— संघ की वार्षिक रिपोर्ट सन् 1995 –96
- 5— सेठ, मीरा सदस्य योजना आयोग, आठवीं पंचवर्षीय योजना, अमर उजाला, बरेली, मई 17, 1995
- 6— नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० लालकुआँ, नैनीताल, प्रगति विवरण, वर्ष 2016–17.